त्योहारों से पहले महंगी होगी चीनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डीजल व रसोई गैस के बाद अब त्योहारी सीजन से ठीक पहले चीनी के दाम बढ़ाने की तैयारी है। अगले मंगलवार को कैबिनेट की होने वाली बैठक में राशन दुकानों से बांटी जाने वाली चीनी की मूल्य वृद्धि पर फैसला हो सकता है। कीमत बढ़ोतरी का यह फैसला एक दशक बाद किया जाएगा।

खाद्य मंत्रालय के कैबिनेट नोट में चीनी के दाम कितने बढ़ाए जाने हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन बिना सब्सिडी वाली चीनी का मूल्य 25.37 रुपये प्रति किलो जरूर बताया गया है। मंत्रालय ने यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया है। फिलहाल, राशन दुकानों से गरीबों को 13.50 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी दी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबों को कुल 27 लाख टन चीनी का वितरण किया जाता है। मिलों को अपने कुल उत्पादन का 10 फीसद चीनी रियायती दर पर सरकार को देना होता है। इसे लेवी चीनी भी कहा जाता है। सरकार मिलों से 19.10 रुपये प्रति किलो के भाव पर चीनी की खरीद करती है। लेकिन गरीब उपभोक्ताओं को 13.50 रुपये से 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। मूल्यों के इस अंतर का भुगतान केंद्रीय सब्सिडी के माध्यम से किया जाता है। खाद्य मंत्रालय के कैबिनेट नोट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस अंतर के भुगतान का बोझ राज्यों पर डाला जाना चाहिए। खासतौर पर शेष पृष्ठ 2 कालम 2 पर

... और तेज किया जाएगा।

त्योहारों से पहले महंगी होगी चीनी

मिलों से चीनी की ढुलाई, उत्पाद शुल्क का भुगतान और अन्य खर्च का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कैबिनेट नोट में यह भी कहा गया है कि चीनी मूल्य में प्रति एक रुपये की वृद्धि से 270 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी कम हो जाएगी। चीनी उद्योग लेवी चीनी की वसूली को लेकर खासा नाराज रहता है। उसका कहना है कि उसे उत्पादन लागत के 60 फीसद पर लेवी चीनी देना पड़ता है। इससे उन्हें सालाना हजारों करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ता है।